Drishti IAS

करेंट अफेयर्स मध्य प्रदेश

अक्तूबर (संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

मध्य प्रदेश **3**

- राज्यपाल ने की सिकल सेल टेस्टिंग मोबाइल वैन लोकार्पित 3
- रायसेन जिले में बम्होरी और सुल्तानगंज बनेगी नई तहसीलें 4
- मुख्यमंत्री ने आजीविका मार्ट और सरस मेले का किया शुभारंभ 4
- मुख्यमंत्री ने प्रदेश के पहले डबल डेकर ओवर ब्रिज का किया भूमिपूजन 5
- मुख्यमंत्री ने इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्वीमिंग पूल का किया लोकार्पण 6
- मुख्यमंत्री ने नीमच में किया प्रदेश के पहले बायोटेक्नालॉजी पार्क का शिलान्यास 7
- मुख्यमंत्री ने भोपाल मेट्रो रेल के ट्रायल रन का किया शुभारंभ 7
- 'जो आया, वो वापस आया' TVC ने IATO सम्मेलन में जीता प्रथम पुरस्कार 10
- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय 10
- खेलो एमपी यूथ गेम्स - 2023 में इंदौर बना ओवरऑल चैंपियन 13
- प्रधानमंत्री ने जबलपुर में 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया 14
- मुख्यमंत्री ने रवाना किये चलित दीनदयाल रसोई केंद्र 16
- वर्ष 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा 17
- केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया मुरैना हार्टिकल्चर कॉलेज का शिलान्यास 18
- मध्य प्रदेश में सीआरसी-छतरपुर के नए भवन की आधारशिला रखी गई 19
- मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन की घोषणा 19
- भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की छठी राज्य रैली प्रतियोगिता 20
- आईआईएसईआर के वैज्ञानिकों ने चुंबकीय छिद्रपूर्ण कार्बन नैनोकणों का उत्पादन किया 22
- सीएम हेल्पलाइन की रैंकिंग में छिंदवाड़ा पहले नंबर पर 23

नोट :

मध्य प्रदेश

राज्यपाल ने की सिकल सेल टेस्टिंग मोबाइल वैन लोकार्पित

चर्चा में क्यों ?

2 अक्तूबर, 2023 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने गांधी जयंती के अवसर पर सिकल सेल टेस्टिंग मोबाइल वैन राजभवन में लोकार्पित की।

प्रमुख बिंदु

- मोबाइल टेस्टिंग वैन रेडक्रॉस की राज्य इकाई द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल को प्रदान की गई है।
- राज्यपाल ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में सिकल सेल नियंत्रण प्रयासों के लिये जनजातीय समुदाय के घर पर विज्ञान को पहुँचाने की दिशा में मोबाइल टेस्टिंग वैन प्रभावी पहल है।
- उन्होंने कहा कि मोबाइल युनिट का संचालन सिकल सेल पीड़ितों के उपचार और वाहक के पुनर्वास प्रयासों को दूरस्थ अंचल में और अधिक प्रभावी बनाएगा।
- मोबाइल टेस्टिंग वैन में सिकल सेल रोग उपचार और पुनर्वास के लिये आवश्यक सभी जाँचों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वैन का संचालन जनजातीय बहुल इलाकों में किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि विगत दिनों एम्स में सिकल सेल वार्ड के उद्घाटन समारोह में भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रबंधकों द्वारा सिकल सेल रोग उपचार और पुनर्वास के लिये वाहन की आवश्यकता का उल्लेख किया गया था।

नोट :

रायसेन ज़िले में बम्होरी और सुल्तानगंज बनेगी नई तहसीलें

चर्चा में क्यों ?

2 अक्तूबर, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में ज़िले के बम्होरी और सुल्तानगंज को तहसील बनाने की घोषणा करते हुए कई अन्य महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ कीं।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में लगभग 100 करोड़ रुपए की सेमरी जलाशय नल-जल प्रदाय योजना का शुभारंभ करने के बाद जनसमुदाय को संबोधित करते हुए ये घोषणाएँ कीं।
- मुख्यमंत्री ने रायसेन ज़िले के बेगमगंज में 99 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से सेमरी जलाशय आधारित समूह नल-जल-प्रदाय योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने 24 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत के 93 नवीन विकास कार्यों का भूमिपूजन तथा शिलान्यास और 28 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से 25 निर्मित विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया।
- सेमरी जलाशय आधारित समूह नल-जल प्रदाय योजना से बेगमगंज के 46 व गैरतगंज के 49 (कुल 95) ग्राम लाभान्वित होंगे। क्षेत्र के 12 हज़ार 61 परिवारों की 76 हज़ार 400 जनसंख्या लाभान्वित होगी।
- सुचारू जलापूर्ति हेतु 32 उच्च स्तरीय आरसीसी टंकी का निर्माण कराया गया है, जिनकी क्षमता एक लाख लीटर से 5.20 लाख लीटर तक है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि बेगमगंज में जनपद का नया भवन तथा ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। बेगमगंज और बम्होरी की शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नये भवन स्वीकृत किये जाएंगे। बेगमगंज, गैरतगंज, सिलवानी और रायसेन नगर पालिका में विकास कार्यों के लिये 5-5 करोड़ रुपए उपलब्ध कराये जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने आजीविका मार्ट और सरस मेले का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

1 अक्तूबर, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल हाट में राज्य स्तरीय आजीविका मार्ट और सरस मेला-2023 का फीता काटकर शुभारंभ किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- आजीविका मार्ट भोपाल हाट परिसर में 49 लाख 34 हज़ार रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। राज्य स्तरीय आजीविका मार्ट में खाद्य पदार्थ, स्वच्छता सामग्री, वस्त्र, सजावटी सामग्री एवं अन्य वस्तुएँ उपलब्ध रहेगी।
- सभी 53 ज़िलों के स्व-सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों का विक्रय किया जाएगा। बिचौलियों के बिना स्व-सहायता समूह की सीधे शहरी उपभोक्ताओं तक पहुँच बनेगी।
- विभिन्न ज़िलों के उत्पादों के वितरण के लिये प्रदेश में 43 रूरल मार्ट संचालित हैं। आजीविका मार्ट इन सभी रूरल मार्ट का समन्वयन केंद्र बनकर उभरेगा।
- पतंजलि आयुर्वेद तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। इससे आजीविका ब्रांड के उत्पादों के मानकीकरण और मार्केटिंग में सहायता मिलेगी।
- प्रदेश में आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्व-सहायता समुहों से जुड़कर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ अनेक उत्पाद बना रही हैं। आजीविका मिशन में अब तक प्रदेश में लगभग 5 लाख महिला स्व-सहायता समूहों का गठन कर 60 लाख से अधिक परिवारों को जोड़ा गया है।
- आजीविका स्टोर भोपाल में मसालें, तेल, घी, आटा, दाल, चावल, नमक, गुड़, आचार, पापड़, टोस्ट, शहद, मिलेट्स आइटम, साबुन, वाशिंग पाउडर, महेश्वरी साड़ी, बाग-प्रिंट, लेडिज ड्रेस मटेरियल, सलवार सूट, पर्स, चादर, स्टॉल, ज्वेलरी, हथकरघा वस्त्र, लोक-कला कीर्ति, टेराकोटा, बांस के आयटम, ट्राइबल ऑर्ट, डिजाइनर झाड़ू, अगरबत्ती, गोबर से निर्मित वस्तुएँ आदि उपलब्ध रहेंगी।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के पहले डबल डेकर ओवर ब्रिज का किया भूमिपूजन

चर्चा में क्यों ?

30 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में प्रदेश के पहले डबल डेकर ओवर ब्रिज का भूमिपूजन किया। इंदौर के विकास के लिये 1483 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का भूमिपूजन/लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- इसमें मुख्य रूप से इंदौर के पहले मल्टी लेयर फ्लाईओवर का भूमिपूजन भी शामिल है। इसे मिलाकर कुल चार फ्लाई ओवर और दो रेलवे ओवरब्रिज का भूमिपूजन हुआ। उन्होंने लगभग 80 करोड़ रुपए लागत की 7 सड़कों का लोकार्पण भी किया।

नोट :

- कुल 1400 करोड़ रुपए लागत के 18 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं 83.48 करोड़ रुपए लागत के 9 विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ।
- मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में अधोसंरचना उन्नयन हेतु कुल 192.24 करोड़ रुपए लागत के विभिन्न कार्यों का भूमिपूजन किया, जिसमें 321 बिस्तरीय नवीन कैंसर अस्पताल भवन, 50 बिस्तरीय सीसीएचबी यूनिट, 1000 सीटेड ऑडिटोरियम, विभिन्न चिकित्सा विभागों हेतु नवीन भवन निर्माण कार्य शामिल हैं।
- इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इंदौर के मूसाखेड़ी चौराहे पर 67 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 6 लेन फ्लाई ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया।
- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मूसाखेड़ी रोड का लोकार्पण भी किया। इससे क्षेत्र के नागरिकों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। मुसाखेड़ी चौराहे पर फ्लाई ओवर बनने से राहगीरों को टैफिक जाम से निजात मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्वीमिंग पूल का किया लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

30 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के पिपल्याहाना में इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा नव-निर्मित अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- लोकार्पित किया गया स्विमिंग पूल अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर तैयार देश का पहला सिंक्रोनाइज स्विमिंग पूल है।
- इस स्विमिंग पूल में हाइविंग पूल, रेसिंग पूल, स्पलैश पूल अलग-अलग बनाए गए हैं। महिलाओं एवं पुरुषों के लिये पृथक्-पृथक् चैंजिंग रूम, लॉकर रूम, वॉशरूम, स्टीम बाथ एवं सोना बाथ बनाए गए हैं।
- स्विमिंग पूल परिसर में ही कैफेटेरिया एवं मल्टी जिम की व्यवस्था भी की जा रही है।
- यह फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्विमिंग (एफआईएनए) के नॉर्म्स अनुरूप तैयार किया गया प्रदेश का एकमात्र स्विमिंग पूल है।
- स्विमिंग पूल 28 करोड़ रुपए की लागत की राशि से निर्मित किया गया है। इसकी दर्शक क्षमता 1200 है।

नोट :

मुख्यमंत्री ने नीमच में किया प्रदेश के पहले बायोटेक्नालॉजी पार्क का शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

30 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ज़िले के जावद क्षेत्र के सरवानिया महाराज में 50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले प्रदेश के पहले बायोटेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास किया। उन्होंने 153 करोड़ 37 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 40 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना से नवीन अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। पार्क में 8 उच्च स्तरीय प्रयोगशालाएँ, इनक्यूबेशन सेंटर होंगे।
- यह पार्क शोधार्थियों, उद्योगपतियों के लिये नई तकनीकी सुविधाओं का केंद्र बनेगा। इससे जैव तकनीकों के व्यवसायीकरण के लिये मार्ग प्रशस्त होगा, बायोटेक क्षेत्र में व्यवसाय के अवसर बढ़ेंगे तथा बायोटेक उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा।
- उद्यमी बायोटेक उत्पाद की कंपनी भी शुरू कर सकेंगे और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। बायोटेक्नोलॉजी पार्क शोधार्थियों, उद्योगपतियों के लिये नई तकनीकी सुविधाओं का केंद्र बनेगा।
- मुख्यमंत्री ने 8 करोड रुपए की लागत से नवनिर्मित शासकीय पॉलीटेक्नीक महाविद्यालय जावद के भवन का लोकार्पण भी किया। इसके साथ ही एक करोड़ 47 लाख रुपए के शासकीय कन्या उ.मा.वि.रतनगढ़, एक करोड़ 47 लाख रुपए के शा.हाई स्कूल सरोदा और 43 लाख की लागत से निर्मित होने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र भवन गरवाडा का भूमिपूजन किया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि जावद कृषि उपज मंडी को हाईटेक बनाया जाएगा तथा नीमच मंडी के लिये भी विशेष योजना बनेगी। जावद नीमच माइक्रो एरिगेशन योजना जल्द ही मंजूर की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने भोपाल मेट्रो रेल के ट्रायल रन का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 3 अक्तूबर, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल मेट्रो रेल के ट्रायल रन का सुभाष नगर डिपो से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल में मेट्रो आरंभ होने से परिवहन की नई क्रांति आएगी और विकास पथ पर भोपाल तीव्रगति से दौड़ेगा। भोपाल मेट्रो का विस्तार सीहोर, मंडीदीप के साथ-साथ रायसेन और विदिशा तक भी किया जाएगा।
- सुभाष नगर से रानी कमलापति स्टेशन तक के पाँच किमी. लंबे मेट्रो के भाग में 5 स्टेशन हैं, जिनकी आधारभूत संरचनाओं का काम प्राकृतिक बाधाओं के बावजूद बहुत तेज़ी से पूरा किया गया।
- मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मेट्रो ट्रेन से समय और पैसा दोनों की बचत होगी। भोपालवासियों को सुरक्षित-सुगम-सुविधापूर्ण सस्ता और सुंदर परिवहन का साधन उपलब्ध होगा और शहर का प्रदूषण भी कम होगा।
- अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न मेट्रो के कोच में स्मार्ट लाईटिंग, एयर कडिंशन्स, स्मार्ट डिस्प्ले, एआई सी.सी.टी.वी. कैमरे आदि की सुविधा होगी।
- लगभग 6 हज़ार 941 करोड़ रुपए की भोपाल मेट्रो परियोजना की कुल लंबाई 31 किमी. होगी, करोंद चौराहे से एम्स तक 16.77 किमी., रत्नागिरि तिराहे से भदभदा चौराहे तक 14.18 किमी. पर यह रेल चलेगी।
- पहले चरण में सुभाष नगर एम्स तक 7 किमी. लंबे रूट पर मेट्रो ट्रेन का संचालन होगा। भोपाल मेट्रो का संपूर्ण संचालन 2024 से प्रारंभ हो जाएगा।
- मेट्रो रेल के स्टेशन भी विशेष होंगे, जहाँ पर लिफ्ट एवं एस्केलेटर आदि की सुविधा, बुजुर्गों के लिये विशेष व्यवस्था और ऑनलाइन टिकिटिंग की सुविधा होगी।

नोट :

दिव्यांग श्री मोहन सिंह को उत्कृष्ट कर्त्तव्यनिष्ठा के लिये दिया गया राज्यस्तरीय स्व. देवी प्रसाद शर्मा पुरस्कार, 2020-21

चर्चा में क्यों ?

- 3 अक्तूबर, 2023 को मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने मंत्रालय में उत्कृष्ट कर्त्तव्यनिष्ठा के लिये सहकारिता विभाग, मंत्रालय में कार्यरत् चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री मोहन सिंह को 'स्व. देवी प्रसाद शर्मा पुरस्कार, 2020-21 'दिया।

प्रमुख बिंदु

- श्री मोहन सिंह को उनकी शारीरिक दिव्यांगता के बावजूद समर्पित भाव के साथ समयबद्ध एवं प्रतिबद्ध कर्त्तव्यनिष्ठा के लिये वर्ष 2020-21 का यह पुरस्कार दिया गया। उन्हें पुरस्कार स्वरूप एक लाख रुपए राशि का चेक एवं प्रमाण-पत्र भी दिया गया।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्वर्गीय देवी प्रसाद शर्मा की स्मृति में की गई पुरस्कार की घोषणा के अनुपालन में राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शासकीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उत्तम कार्यों के लिये 'स्व. देवी प्रसाद शर्मा 'पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2017 से की गई है।
- इस पुरस्कार का उद्देश्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उत्तम कार्य के लिये प्रोत्साहित करना है।
- चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में कार्य के प्रति लगनशीलता, समय की पाबंदी, आचरण, व्यवहार, आज्ञाकारिता, कार्यालय में उपस्थिति, अतिरिक्त कार्य लेने के प्रति तत्परता, सौंपे गए कार्य को करने की समझ और योग्यता, स्वच्छता एवं साफ-सफाई के लिये किये गए उत्तम कार्यों के लिये यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
- यह पुरस्कार दिये जाने वाले वर्ष के ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष में किये गए कार्यों के लिये प्रदान किया जाता है।
- यह पुरस्कार राज्यस्तरीय है और इसके अंतर्गत एक लाख रुपए की राशि एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

नोट :

'जो आया, वो वापस आया' TVC ने IATO सम्मेलन में जीता प्रथम पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा लॉन्च किये गए नए TVC 'जो आया, वो वापस आया, ये है एमपी की माया'को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (IATO) के वार्षिक सम्मेलन में डिजिटल मीडिया एडवरटाइजिंग कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार मिला है।

प्रमुख बिंदु

- प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड, शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि प्रदेश के रमणीय पर्यटन स्थलों को देश-विदेश में प्रचारित करने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग द्वारा रचनात्मक प्रयोग किये जाते रहे हैं। नए TVC में गोंड पेंटिंग के माध्यम से पर्यटन स्थलों और पात्रों को दर्शाया गया है।
- एक संगीतमय कहानी के ज़रिये प्रदेश की समृद्ध जनजातीय कला और पर्यटन स्थलों को प्रमुखता से दर्शाया गया है।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूब पर देशभर से 1 करोड़ 30 लाख से अधिक व्यू मिल चुके हैं। यू-ट्यूब पेज पर TVC को 13 लाख 80 हज़ार व्यू, इंस्टाग्राम पर 55 लाख, फेसबुक पर 65 लाख, ट्वीटर पर 6 लाख 79 हज़ार से अधिक व्यू मिल चुके हैं।

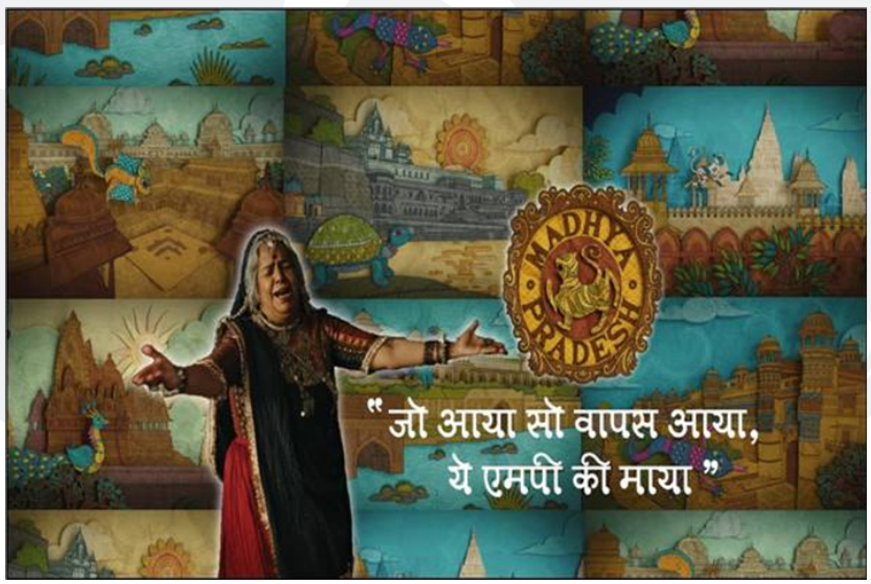

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

4 अक्तूबर, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास 'समत्व भवन'में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रि-परिषद द्वारा 6 हज़ार करोड़ रुपए की 18 सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति देने के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रि-परिषद द्वारा स्वीकृत 18 सिंचाई परियोजनाओं में चितावद-उज्जैन, मेढ़ा-बैतूल, पन्हेटी-गुना, लोनी-रीवा, खाम्हा-कटनी, डोकरीखेड़ी-नर्मदापुरम, सोनपुर-शिवपुरी, थावर-मंडला, मुरकी-डिंडोरी, पावा-शिवपुरी, सिरमौर-रीवा, कनेरा-भिंड, मल्हारगढ़-मंदसौर, देवरी-नर्मदापुरम, सीतलझिरी-बैतूल, आहू-आगर मालवा, बगलीपीठ-बालाघाट और पहाड़िया-रीवा शामिल हैं।
  - इन परियोजनाओं से 02 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि होगी। इससे लगभग 1250 ग्रामों के लगभग 02 लाख कृषक लाभान्वित होंगे।

नोट :

- मंत्रि-परिषद द्वारा छिंदवाड़ा ज़िले की तहसील सोंसर एवं पांढुर्ना को समाविष्ट कर नवीन ज़िला पाढुर्ना बनाने की स्वीकृति दी गई है।
- मंत्रि-परिषद द्वारा ज़िला उज्जैन में नवीन तहसील उन्हेल, ज़िला बालाघाट में नवीन तहसील लामता, ज़िला रायसेन में नवीन तहसील बम्होरी एवं सुल्तानगंज तथा ज़िला मंदसौर में नवीन तहसील कयामपुर के गठन को स्वीकृति दी गई।
- मंत्रि-परिषद द्वारा मंदसौर ज़िले की ग्राम पंचायत नाहरगढ़, बोलिया एवं गांधीसागर, सीधी ज़िले की ग्राम पंचायत सेमरिया, शाजापुर ज़िले की ग्राम पंचायत अवंतिपुर बड़ोदिया एवं गुलाना, सतना ज़िले की ग्राम पंचायत सिंहपुर, हरदा ज़िले की ग्राम पंचायत रहटगाँव को नगर परिषद के रूप में गठन एवं शहडोल ज़िले की नगर परिषद ब्यौहारी को नगर पालिका परिषद में उन्नयन किये जाने तथा राज्यपाल को प्रेषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- कमला पार्क से संत हिरदाराम नगर तक एलिवेटेड कॉरिडोर की स्वीकृति: मंत्रि-परिषद द्वारा भोपाल से इंदौर, राजगढ़ एवं पुराने भोपाल में यातायात सुगम करने के लिये 8-लेन मार्ग के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। मार्ग का निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के अंतर्गत किया जाएगा। परियोजना के क्रियान्वयन के लिये 3 हज़ार 156 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया।
- मंत्रि-परिषद द्वारा सेवामुक्त होने पर कोटवार को निर्धारित नियमों के अंतर्गत एक लाख रुपए की राशि दिये जाने की स्वीकृति दी गई।
- पैक्स और लैंपस की प्रबंधकीय अनुदान की राशि में अतिरिक्त वार्षिक वृद्धि करने का निर्णय: मंत्रि-परिषद द्वारा सहकारिता विभाग की योजना के अंतर्गत प्राथमिक साख सहकारी समितियों (पैक्स) एवं आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों (लैंपस) को दिये जाने वाले प्रबंधकीय अनुदान की राशि में प्रति समिति 3 लाख रुपए की अतिरिक्त वार्षिक वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया।
  - इसके साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकानों के संचालन के लिये पैक्स एवं लैंपस समितियों के विक्रेताओं को भी 3 हज़ार रुपए प्रति विक्रेता प्रति माह पारिश्रमिक मानदेय बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है।
  - योजना का क्रियान्वयन 01 अक्तूबर, 2023 से किया जाएगा।
- स्कूटी प्रदाय योजना के सरलीकरण की स्वीकृति: मंत्रि-परिषद द्वारा सभी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा एवं छात्र को नि:शुल्क ई-स्कूटी/स्कूटी के क्रय करने की कार्यवाही के सरलीकरण के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
- तीन सिंचाई परियोजनाओं की निविदा आमंत्रित करने की अनुमति: मंत्रि-परिषद द्वारा नर्मदा घाटी विकास विभाग की 3 परियोजनाओं क्रमश: बहोरीबंद माइक्रो सिंचाई परियोजना, शहीद इलाप सिंह उदवहन माइक्रो सिंचाई परियोजना और खंडवा उदवहन माइक्रो सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति एवं निविदा आमंत्रित करने की अनुमति प्रदान की गई।
  - लगभग 1,12,220 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित करने वाली तीनों परियोजनाओं की लागत राशि 3 हज़ार 598 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई।
- आहार अनुदान योजना की हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि में वृद्धि की स्वीकृति: मंत्रि-परिषद द्वारा आहार अनुदान योजना की हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि में 250 रुपए की वृद्धि करते हुए प्रतिमाह राशि 1250 रुपए के स्थान पर 1500 रुपए प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति दी गई है।
- विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये केवल एक बार ही शुल्क लिये जाने की स्वीकृति: मंत्रि-परिषद द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये केवल एक बार ही शुल्क लिये जाने के संबंध में प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया गया। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिये वन टाईम परीक्षा शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रारंभ की जा रही है।
- शहीद हुए वनकर्मियों को 25 लाख विशेष अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति: मंत्रि-परिषद द्वारा शहीद हुए वनकर्मियों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा शहीद घोषित करते हुए आश्रितों को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए विशेष अनुग्रह अनुदान प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।
- जनजातीय कार्य विभाग के 95 सीएम राइज स्कूलों के चयन एवं स्थान परिवर्तन का अनुसमर्थन: मंत्रि-परिषद द्वारा जनजातीय कार्य विभाग के 95 सीएम राइज स्कूलों के चयन एवं स्थान परिवर्तन का अनुसमर्थन किया गया।
- जनजातीय एवं लोक कलाकारों को प्रदर्शन के लिये दैनिक मानदेय एवं भत्ते की दरों में वृद्धि की स्वीकृति: मंत्रि-परिषद ने जनजातीय एवं लोक कलाकारों को प्रदर्शन के लिये दैनिक मानदेय एवं भत्ते की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी है।
  - कलाकारों को प्रदर्शन के लिये दैनिक मानदेय 800 रुपए प्रति दिवस से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति दिवस एवं दैनिक भत्ता 250 रुपए प्रति दिवस से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिवस किया गया।

नोट :

- लोक कलाकारों को आवागमन, स्थानीय परिवहन तथा आवास सुविधा पूर्ववत् जारी रखी जाएगी।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियों में प्रतिभागिता हेतु जाने वाले कलाकारों तथा उनके समन्वय हेतु जाने वाले विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को भेजे जाने के लिये संस्कृति विभाग सक्षम प्राधिकारी होगा।

- विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र की स्थापना की स्वीकृति: मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के 52 ज़िला मुख्यालयों पर युवाओं के लिये 'विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र'की स्थापना की स्वीकृति दी है। विवेकानंद युवा संसाधन केंद्र में भौतिक स्वरूप, त्रिस्तरीय समितियाँ होंगी।
- कर्मचारियों को आयुष्मान भारत 'निरामयम'प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना में शामिल करने की स्वीकृति: मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारी/कार्यकर्त्ता/संविदा कर्मियों को आयुष्मान भारत 'निरामयम'प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति दी है।
  - भारत निरामयम योजना के अंतर्गत स्वीकृत पात्र हितग्राही, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोज़गार सहायक, आशा तथा ऊषा कार्यकर्त्ता, आशा सुपरवाईजर, कोटवार एवं संविदा कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत किया गया है।
- अन्य निर्णय
  - मंत्रि-परिषद द्वारा भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय की पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्र) योजना के अंतर्गत प्रदेश में टेक्सटाईल पार्क की स्थापना के लिये एसपीवी (विशेष प्रयोजन वाहन) के गठन संबंधी जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, मेमोरेंडम तथा आर्टीकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रारूप के अनुमोदन के संबंध में निर्णय लिया गया है।
  - मंत्रि-परिषद द्वारा महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यलाय उज्जैन का कैम्पस ज़िला रीवा में भी स्थापित करने की स्वीकृति दी गई।
  - मंत्रि-परिषद द्वारा अमरपाटन ज़िला मैहर में नवीन शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी गई।
  - मंत्रि-परिषद द्वारा रायसेन ज़िले में 100 एम.बी.बी.एस. सीट प्रवेश क्षमता के नवीन मेडिकल कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति दी गई।
  - मंत्रि-परिषद द्वारा मेडिकल कॉलेज के शैक्षणिक संवर्ग को वर्ष 2016 से 7वाँ वेतनमान दिये जाने की स्वीकृति दी गई।
  - वनरक्षकों को प्रशिक्षण पूर्ण होने की दिनांक से मूल वेतन स्वीकृत किये जाने की स्वीकृति दी गई है।

नोट :

खेलो एमपी यूथ गेम्स - 2023 में इंदौर बना ओवरऑल चैंपियन

चर्चा में क्यों ?

5 अक्तूबर, 2023 को मध्य प्रदेश में टी.टी. नगर स्टेडियम, भोपाल में पहले खेलो एमपी यूथ गेम्स-2023 का समापन हुआ, जिसमें इंदौर ज़िले ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप की ट्रॉफी प्राप्त की।

प्रमुख बिंदु

- इंदौर 42 स्वर्ण, 32 रजत और 24 काँस्य सहित कुल 98 पदक लेकर पहले स्थान पर रहा। जबलपुर 24 स्वर्ण, 27 रजत और 35 काँस्य पदक, कुल 86 पदक लेकर दूसरे स्थान पर रहा। भोपाल ने 24 स्वर्ण, 27 रजत और 35 काँस्य पदक लेकर कुल 77 पदक के साथ तीसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई। उज्जैन 9 स्वर्ण, 13 रजत और 17 काँस्य पदक सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा।
- खेलो एमपी यूथ गेम्स में दलीय एवं व्यक्तिगत खेल के खिलाड़ियों को प्रथम पुरस्कार 31 हज़ार रुपए, द्वितीय पुरस्कार 21 हज़ार रुपए, तृतीय और चतुर्थ पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों को 11 हज़ार रुपए से पुरस्कृत किया गया। एमपी यूथ गेम्स में कुल 2 करोड़ रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में वितरित की गई।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में पहली बार हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स की सफलता के बाद घोषणा की थी कि 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स' की तर्ज पर मध्य प्रदेश में 'खेलो एमपी यूथ गेम्स'का आयोजन भी किया जाएगा। इस कड़ी में 12 से 28 सितम्बर तक प्रदेश में विभिन्न चरणों में खेल प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं।
- खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन प्रदेश के सभी 52 ज़िलों के 313 विकासखंडों में किया गया।
- यूथ गेम्स 4 चरणों, ब्लॉक, ज़िला, संभाग एवं राज्य-स्तर पर किया गया। ब्लॉक-स्तरीय चयन स्पर्धा 12 से 14 सितंबर, ज़िला-स्तरीय प्रतियोगिता 16 से 18 सितंबर, संभाग-स्तरीय 20 से 23 सितंबर तथा राज्य-स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन 1 से 5 अक्तूबर तक किया गया।
- राज्य-स्तर पर प्रदेश के 8 संभाग भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन एवं शहडोल की टीमों ने सहभागिता की।
- 24 खेलों में राज्य-स्तरीय प्रतियोगिताएँ प्रदेश के 7 शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुरी, उज्जैन, रीवा एवं जबलपुर में हुईं।
- ज़िला एवं संभाग स्तर पर प्रदेश में प्रचलित 18 खेल एथलेटिक्स, बॉस्केट-बॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो-खो, मलखंब, तैराकी, वेट-लिफ्टिंग, कुश्ती, टेबिल-टेनिस, योगासन, व्हॉलीबॉल, टेनिस और शतरंज का आयोजन किया गया।
- राज्य-स्तर पर 6 खेल ताइक्वांडो, फैंसिंग, रोइंग, क्याकिंग-कनोइंग, शूटिंग एवं आर्चरी जैसे खेलों का आयोजन किया गया।
- राज्य-स्तर पर एथलेटिक्स, शूटिंग प्रतियोगिताएँ स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स शिवपुरी में हुईं। भोपाल के टी.टी. नगर स्टेडियम में बॉक्सिंग, ताक्वांडो, जूडो, फैंसिंग, टेनिस, फुटबॉल, व्हॉलीबॉल, कुश्ती, शतरंज प्रतियोगिताएँ खेली गईं।
- भोपाल की बड़ी झील में कयाकिंग-केनोइंग और रोइंग तथा प्रकाश तरण पुष्कर में तैराकी प्रतियोगिता, इंदौर के बॉस्केट-बॉल कॉम्प्लेक्स में बॉस्केट-बॉल और वेट-लिफ्टिंग प्रतियोगिताएँ तथा एमरॉल्ड हाइट्स स्कूल में टेबल-टेनिस के मुकाबले हुए।
- ग्वालियर में मध्य प्रदेश बैडमिंटन अकादमी बेडमिंटन और मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी कम्पू ग्वालियर में हॉकी की प्रतियोगिताएँ, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स उज्जैन में मलखंब और योगासन, जबलपुर के रानीताल स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स में खो-खो एवं तीरंदाजी तथा स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स रीवा में कबड्डी के शानदार मुकाबले खेले गए।

नोट :

प्रधानमंत्री ने जबलपुर में 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया

चर्चा में क्यों ?

5 अक्तूबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क, रेल, गैस पाइपलाइन, आवास और स्वच्छ पेयजल जैसे क्षेत्रों की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया।

प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री ने रानी दुर्गावती के 500वें जन्म शताब्दी समारोह के अनुरूप जबलपुर में 'वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान'का भूमि पूजन किया।
- जबलपुर में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 'वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान'लगभग 21 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत होगा। इसमें रानी दुर्गावती की 52 फुट ऊँची काँस्य प्रतिमा प्रदर्शित की जाएगी।
- इस परिसर में रानी दुर्गावती की वीरता और साहस सहित गोंडवाना क्षेत्र के इतिहास को दिखाने वाला एक शानदार संग्रहालय होगा। यह गोंड लोगों और अन्य जनजातीय समुदायों के खान-पान, कला, संस्कृति, रहन-सहन आदि पर भी प्रकाश डालेगा।
- 'वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान'के परिसर में औषधीय पौधों के लिये एक उद्यान, एक कैक्टस उद्यान और रॉक गार्डन सहित कई पार्क एवं उद्यान मौजूद होंगे।
- उल्लेखनीय है कि रानी दुर्गावती 16वीं शताब्दी के मध्य में गोंडवाना की शासिका थीं। उन्हें एक बहादुर, निडर और साहसी योद्धा के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत लगभग 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट से 1000 से अधिक लाभार्थी परिवारों को फायदा होगा। लेकिन गुणवत्तापूर्ण घर बनाने की इस परियोजना में अभिनव प्रौद्योगिकी, 'पूर्व-तकनीक आधारित इस्पात संरचना प्रणाली के साथ प्रीफैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम'का उपयोग किया गया है। इस अभिनव प्रौद्योगिकी से काफी कम समय में सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ आवास निर्मित किये जाते हैं।
- प्रत्येक परिवार को नल से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने लिये मंडला, जबलपुर और डिंडोरी ज़िलों में 2350 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई जल जीवन मिशन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री ने सिवनी ज़िले में भी 100 करोड़ रुपए से अधिक की जल जीवन मिशन परियोजना का लोकार्पण किया। राज्य के चार ज़िलों की इन परियोजनाओं से मध्य प्रदेश के लगभग 1575 गाँवों को लाभ होगा।

नोट :

- प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में सड़क अवसंरचना में सुधार के लिये 4800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।
- प्रधानमंत्री ने विभिन्न सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिनमें शामिल हैं - एनएच 346 के झरखेड़ा-बैरसिया-ढोलखेड़ी को जोड़ने वाली सड़क का उन्नयन; एनएच 543 के बालाघाट-गोंडिया खंड का चार लेन में उन्नयन; रूढ़ी और देशगाँव को जोड़ने वाले खंडवा बाईपास को चार लेन का बनाना; एनएच 47 के टेमागाँव से चिचोली खंड को चार लेन का बनाना; बोरेगाँव को शाहपुर से जोड़ने वाली सड़क को चार लेन का बनाना और शाहपुर को मुक्ताईनगर से जोड़ने वाली सड़क को चार लेन का बनाना। प्रधानमंत्री ने एनएच 347सी के खलघाट से सरवरदेवला को जोड़ने वाली सड़क के उन्नयन का लोकार्पण किया।
- प्रधानमंत्री ने 1850 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित कीं। इनमें कटनी-विजयसोटा (102 किमी.) और मारवासग्राम-सिंगरौली (78.50 किमी.) को जोड़ने वाली रेल लाइनों का दोहरीकरण शामिल हैं। ये दोनों परियोजनाएं कटनी-सिंगरौली खंड को जोड़ने वाली रेल लाइन के दोहरीकरण की परियोजना का हिस्सा हैं। इन परियोजनाओं से मध्य प्रदेश की रेल अवसंरचना में सुधार होगा, जिससे राज्य में व्यापार और पर्यटन को लाभ होगा।
- प्रधानमंत्री ने विजयपुर-औरैयां-फूलपुर पाइपलाइन परियोजना का लोकार्पण किया। 352 किमी लंबी पाइपलाइन 1750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित की गई है। प्रधानमंत्री ने मुंबई-नागपुर-झारसुगुड़ा पाइपलाइन परियोजना के नागपुर-जबलपुर खंड (317 किमी.) की आधारशिला भी रखी। यह परियोजना 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से पूरी की जाएगी।
- गैस पाइपलाइन परियोजनाएँ उद्योगों और घरों को स्वच्छ व किफायती प्राकृतिक गैस प्रदान करेंगी और पर्यावरण में उत्सर्जन को कम करने में भी मददगार होंगी। प्रधानमंत्री ने जबलपुर में एक नए बॉटलिंग प्लांट का भी लोकार्पण किया, जो लगभग 147 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है।

नोट :

राष्ट्रीय सांस्कृतिक समारोह में 23 प्रतियोगिताएँ जीत कर दूसरे स्थान पर रहे मध्य प्रदेश के जनजाति वर्ग के विद्यार्थी

चर्चा में क्यों ?

7 अक्तूबर, 2023 को मध्य प्रदेश के जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों ने देहरादून में ई.एम.आर.एस. के चौथे राष्ट्रीय सांस्कृतिक समारोह में 23 प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

प्रमुख बिंदु

- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ई.एम.आर.एस.) के विद्यार्थियों ने देश में ओवरऑल दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश से सिर्फ एक प्रतियोगिता अधिक जीतने पर उत्तराखंड ओवरऑल चैंपियन बना।
- मध्य प्रदेश के 80 विद्यार्थियों ने इस समारोह में 28 विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिसमें 23 में से 10 प्रतियोगिताओं में प्रथम, 07 में द्वितीय और 06 में तृतीय स्थान प्राप्त किया।
- चार दिवसीय आयोजन में देश के 22 राज्यों के 2200 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने रवाना किये चलित दीनदयाल रसोई केंद्र

चर्चा में क्यों ?

7 अक्तूबर, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट पार्क से चलित दीनदयाल रसोई केंद्र को झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रमुख बिंदु

- ये चलित केंद्र भोपाल और अन्य शहरों के उन स्थानों पर जाकर श्रमिकों और अन्य ज़रूरतमंद लोगों को पाँच रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध करवाएंगे, जहाँ ये लोग कार्य करते हैं। प्रदेश के अन्य नगरों में भी चलित केंद्र संचालित किये जाएंगे।
- इस योजना को प्रारंभ करने के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। एक यह कि रियायती दर पर गरीब व्यक्ति को भोजन मिल सके, दूसरा प्रवासी श्रमिक और अन्य ज़रूरतमंद नागरिकों को कार्य स्थल के नज़दीक भरपेट भोजन की सुविधा मिल सके।

नोट :

- पूर्व में संचालित केंद्र एक स्थान पर ही होते थे। इस व्यवस्था से ऐसे मज़दूर, जो गाँव से शहर आकर जीविका चलाते हैं, उन्हें अधिक राशि और समय खर्च किये बिना उनके काम करने की जगह पर ताजा भोजन उपलब्ध हो जाएगा।
- इन केंद्रों में 5 रुपए थाली की दर से सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक भोजन का वितरण किया जाता है। राज्य सरकार ने इस योजना में प्रति व्यक्ति 10 रुपए के मान से अनुदान देने की व्यवस्था की है।
- उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में 7 फरवरी, 2017 में यह योजना ज़िला मुख्यालयों और 6 प्रमुख धार्मिक स्थानों को मिलाकर 56 स्थानों पर संचालन के साथ प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में 166 स्थानों पर योजना का संचालन किया जा रहा है।
- इस योजना में प्रदेश में सवा दो सौ लाख भोजन थालियों का वितरण किया जा चुका है।
- प्रदेश में 25 चलित रसोई केंद्र प्रारंभ हुए हैं। एक चलित केंद्र की लागत 25 लाख रुपए है। इसमें खाना तैयार करने और गर्म खाना रखने के आधुनिक उपकरण भी रहेंगे।
- प्रदेश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले जिन नगरों में चलित केंद्र शुरू हुए हैं, उनमें भोपाल में 3, इंदौर में 4, जबलपुर, ग्वालियर में दो-दो चलित रसोई केंद्र शामिल हैं। शेष 12 नगर निगमों और 2 औद्योगिक नगरों पीथमपुर एवं मंडीदीप में एक-एक चलित रसोई केंद्र का संचालन शुरू किया गया है।
- शीघ्र ही 20 हज़ार से अधिक आबादी वाले 68 नगरीय निकायों में भी इस तरह के रसोई केंद्र शुरू करने की योजना है।

वर्ष 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा

चर्चा में क्यों ?

6 अक्तूबर, 2023 को मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने वर्ष 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2022 के लिये राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र को और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को प्रदान किया जाएगा।

नोट :

- संस्कृति विभाग द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय एवं राज्य सम्मानों की सम्मान राशि वर्ष 2022 से दोगुनी कर दी गई है। अब राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान एवं राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान में 5 लाख रुपए की सम्मान राशि, सम्मान पटिका एवं शॉल-श्रीफल प्रदान किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान भी बारी-बारी से पार्श्व गायन एवं संगीत निर्देशन के क्षेत्र में दिया जाता है। वर्ष 2022 का यह सम्मान संगीत निर्देशन के लिये दिया जाना था।
- प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान के लिये चुना गया है। वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान फिल्म अभिनय के क्षेत्र में दिया जाना था। यह सम्मान बारी-बारी से अभिनय, पटकथा, गीत लेखन एवं निर्देशन के क्षेत्र में दिया जाता है।

विख्यात संगीत निर्देशक और प्रसिद्ध वायलिन वादक उत्तम सिंह ने बॉलीवुड की कई फिल्मों के लिये म्यूजिक अरेंजर, प्रोग्रामर और रिकॉर्डिस्ट के रूप में भी काम किया है।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया मुरैना हार्टिकल्चर कॉलेज का शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

6 अक्तूबर, 2023 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झाँसी के अंतर्गत मुरैना ज़िले की पोरसा तहसील के ग्राम रतन बसई में स्थापित होने वाले हार्टिकल्चर कॉलेज का शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- 160 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस कॉलेज में स्नातक की शिक्षा देने के साथ ही कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को खेती संबंधी प्रशिक्षण देते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।
- 300 एकड़ में बनने वाले इस कॉलेज से क्षेत्र का विस्तार-विकास होगा। इस कॉलेज से चंबल-ग्वालियर क्षेत्र सहित मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान व उत्तर प्रदेश के कई ज़िले भी लाभान्वित होंगे। शोध कार्यों के लिये भी कॉलेज के माध्यम से किसानों व क्षेत्र को लाभ होगा।
- इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यह कॉलेज क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने के साथ ही किसानों के लिये कल्याणकारी होगा। इससे युवाओं के लिये नए रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे, वहीं ये किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी सहायक होगा।
- खेती-किसानी में नई फसलें और टेक्नोलॉजी आने के साथ मुनाफा बढ़ेगा, जिससे युवा पीढ़ी खेती की ओर अधिक आकर्षित होगी।

नोट :

मध्य प्रदेश में सीआरसी-छतरपुर के नए भवन की आधारशिला रखी गई

चर्चा में क्यों ?

6 अक्तूबर, 2023 को समावेशिता और सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ी छलांग के प्रतीक के रूप में मध्य प्रदेश में समग्र क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी)-छतरपुर के नए भवन की आधारशिला रखी गई।

प्रमुख बिंदु

- इस दूरदर्शी परियोजना के लिये अनुमानित निर्माण लागत 25 करोड़ रुपए है और शीघ्र निर्माण कार्य शुरू करने के लिये एनबीसीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पहले ही किया जा चुका है।
- केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने सीआरसी-छतरपुर के नए भवन की आधारशिला रखने के अलावा छतरपुर में 9 करोड़ रुपए की लागत वाले संवेदी पार्क की भी आधारशिला रखी। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तीकरण के लिये ज़िला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन भी किया।
- सीआरसी-छतरपुर के उद्घाटन समारोह में कैबिनेट मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि यह भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एक और अग्रणी पहल है। यह कौशल विकास, पुनर्वास सेवाओं और समावेशी सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिये प्रतिबद्ध है।
- राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) द्वारा निर्माण कार्य को 18 महीनों में पूरा किया जाएगा। यह आगामी संरचना 41,275 वर्गफीट के विशाल क्षेत्र में होगी और इसे सुगम्यतापूर्ण माहौल प्रदान करने के लिये तैयार किया जाएगा, जो दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन की घोषणा

चर्चा में क्यों ?

9 अक्तूबर, 2023 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मध्य प्रदेश में निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू करने की घोषणा की।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन के कार्यक्रम अनुसार 17 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 3 दिसंबर को होगी।
- निर्वाचन की अधिसूचना 21 अक्तूबर को जारी होगी और 30 अक्तूबर तक नामांकन पत्र जमा किये जा सकेंगे। आवेदनों की संवीक्षा 31 अक्तूबर को होगी और 2 नवंबर को नाम वापसी के साथ ही प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होगी।
- उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 60 लाख 60 हज़ार 925 मतदाता फोटो निर्वाचक नामावली में नामांकित हैं। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 88 लाख 25 हज़ार 607, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 72 लाख 33 हज़ार 945 है। थर्ड जेंडर मतदाता एक हज़ार 373 है।
- प्रदेश में 64 हज़ार 523 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। शहरी क्षेत्र में 16 हज़ार 763 और ग्रामीण क्षेत्र में 47 हज़ार 760 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर शौचालय, रैंप, व्हील चेयर, पानी, हेल्पडेस्क, बिजली आदि की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) मतदाताओं के लिये मतदान केंद्र भूतल पर बनाए गए हैं। इन्हें घर से भी मतदान करने की सुविधा (पोस्टल बैलेट) दी गई है। ऐसे मतदाताओं को फॉर्म 12 डी भरकर देना होगा।
- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जीपीएस आधारित सी-विजिल ऐप में 2 मिनट का वीडियो और फोटो डाउनलोड किये जा सकेंगे। कोई भी नागरिक आयोग को ऐप के माध्यम से शिकायत प्रेषित कर सकेगा।

भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की छठी राज्य रैली प्रतियोगिता

चर्चा में क्यों ?

12 अक्तूबर, 2023 को भोपाल के हबीबगंज रेलवे कॉलोनी स्थित खेल मैदान में पश्चिम मध्य रेल, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स द्वारा आयोजित छठवीं राज्य रैली प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रतियोगिता की शुरुआत 09 अक्तूबर को हुई थी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस प्रतियोगिता में गायन, वादन, नुक्कड़ नाटक, लोकनृत्य, रंगोली, प्रदर्शनी, पिरामिड, मार्चपास्ट जैसी प्रतियोगिताएँ शामिल थीं। इस रैली में जबलपुर, कोटा, भोपाल से लगभग 385 प्रतिभागी भाग लेने पहुँचे थे।
- इस प्रतियोगिता में राज्य मुख्य आयुक्त शील्ड सर्वाधिक सेंसेस वाले मंडल जबलपुर को दी गई।
- कोटा रेल मंडल ने बाजी मारते हुए सभी 20 प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान लेकर ओवरऑल चैंपियन शील्ड जीती। भोपाल मंडल को द्वितीय व जबलपुर मंडल को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ।
- राज्य पुरस्कार प्रमाण-पत्र चार प्रतिभागियों- अंस करमारकर, आस्था करमारकर, अंजली नेगी और सोनम असीम को प्रदान किया गया।

80 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं को मिलेगी पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा

चर्चा में क्यों ?

13 अक्तूबर, 2023 को राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि सभी ज़िला निर्वाचन अधिकारी ऐसे पात्र मतदाताओं को फॉर्म 12 डी का वितरण बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से कराएँ।
- साथ ही अनुपम राजन ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के मतदाता, 40 प्रतिशत से अधिक के दिव्यांग मतदाता या अत्यावश्यक सेवाओं में संलग्न मतदाता के नाम से पोस्टल बैलेट जारी हो गया है, तो फिर वह किसी भी मतदान केंद्र में जाकर मतदान नहीं कर सकेगा।

नोट :

- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नागरिकों के लिये सी-विज़िल ऐप बनाया गया है। कोई भी नागरिक सी-विज़िल ऐप के माध्यम से आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकता है।
- नागरिक स्मार्ट मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सी-विज़िल ऐप को डाउनलोड कर सकता है। 100 मिनट में शिकायत का निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कलेक्टर्स एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को सी-विज़िल ऐप से मिलने वाली शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिये।

आईआईएसईआर के वैज्ञानिकों ने चुंबकीय छिद्रपूर्ण कार्बन नैनोकणों का उत्पादन किया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल (आईआईएसईआर) के शोधकर्त्ताओं ने सफलतापूर्वक चुंबकीय नैनोकणों का उत्पादन किया है, जो मानव बाल की चौड़ाई से लगभग एक लाख गुना छोटे कण हैं।

प्रमुख बिंदु

- इन नैनोकणों को कई अनुप्रयोगों के लिये विकसित किया गया है, जैसे- समुद्री जल से गर्मी और प्रकाश-प्रेरित नमक को हटाना, रंगों और डीसिंग और एंटी-आइसिंग प्रक्रियाओं से दूषित अपशिष्ट जल से पीने योग्य पानी निकालना।
- दुनिया की प्राथमिक वैश्विक चुनौतियों में से एक अपशिष्ट जल और समुद्री जल जैसे स्रोतों से स्वच्छ और उपयोग योग्य ताजा जल प्राप्त करना है। ऐसा अनुमान है कि दुनिया की लगभग दो-तिहाई आबादी जल्द ही पानी की कमी की समस्या वाले क्षेत्रों में रहेगी।
- विदित है कि अलवणीकरण, एक ऐसी प्रक्रिया, जो लगभग 40% तटीय समुदायों के लिये स्थानीय जल स्रोत प्रदान कर सकती है। समुद्री जल से उपयोग योग्य पानी का उत्पादन करने वाली अलवणीकरण विधियों में आमतौर पर ऐसी प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं, जिनमें बहुत अधिक हीट की आवश्यकता होती है, जैसे- आसवन या रिवर्स ऑस्मोसिस जैसी झिल्ली-आधारित तकनीकें।
- हालाँकि, इन विधियों के लिये अक्सर महँगे उपकरण, बड़े सेटअप और पर्याप्त ऊर्जा खपत की आवश्यकता होती है। एक अधिक टिकाऊ विकल्प फोटोथर्मल (प्रकाश+ताप)--सहायक अलवणीकरण है, जो नवीकरणीय सौर ऊर्जा का उपयोग करता है।
- कुशल अलवणीकरण प्रक्रियाओं से लेकर डाई हटाने और डी-आइसिंग तक विविध अनुप्रयोगों के साथ चुंबकीय नैनोकणों का निर्माण टिकाऊ और सुलभ जल संसाधनों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। विज्ञान में इस तरह की प्रगति एक ऐसे भविष्य की आशा प्रदान करती है, जहाँ दुनिया भर के समुदायों के लिये स्वच्छ और सुरक्षित पानी अधिक आसानी से उपलब्ध होगा।
- इस अनुसंधान का नेतृत्व आईआईएसईआर भोपाल के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. शंकर चकमा ने किया।
- इस शोध समूह के निष्कर्ष प्रतिष्ठित सहकर्मी-समीक्षा पत्रिका अमेरिकन केमिकल सोसाइटी - ईएसटी इंजीनियरिंग में प्रकाशित हुए हैं।

नोट :

सीएम हेल्पलाइन की रैंकिंग में छिंदवाड़ा पहले नंबर पर

चर्चा में क्यों ?

21 अक्तूबर, 2023 को मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने सितंबर, 2023 महीने की सीएम हेल्पलाइन की रैंकिंग जारी कर दी है।

प्रमुख बिंदु

- 16 नगर निगमों में छिंदवाड़ा पहले नंबर पर और बुरहानपुर दूसरे नंबर पर रहा, जबकि उज्जैन ने तीसरा स्थान पाया है और चार महानगरों में सिर्फ जबलपुर टॉप फाइव में आया है।
- ग्वालियर इस सूची में 10वें स्थान पर है। उसे 'ए' ग्रेड भी दिया गया है। हालाँकि 16 नगर निगम में 13 को 'ए' ग्रेड और तीन को 'बी' ग्रेड मिला है।
- भोपाल छठवें और इंदौर 13वें नंबर पर रहा, जबकि मुरैना नगर निगम 16 नगरीय निकाय में सबसे निचले स्थान पर है।
- इस रैंकिंग में प्रदेश के ये 16 नगर निगम शामिल हैं- ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, उज्जैन, रतलाम, सिंगरौली, खंडवा, सागर, कटनी, देवास, रीवा, सतना और मुरैना।
- 16 नगर निगम में सबसे ज़्यादा सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें भोपाल में 3872, इंदौर में 3637, जबलपुर में 2510, ग्वालियर में 2447 हैं, जबकि सबसे कम शिकायतें बुरहानपुर में 201 आईं।

दृष्टि The Vision

नोट :